स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). दिल्ली तथा इसके साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को अभी मूर्त रूप नहीं दिया गया है। मेरठ, बुलन्दशहर गुड़गांव या रोहतक जिलों के किसानों की भूमि को सरकार ने हाथ मे नही लिया है। इस प्रकार, उक्त उद्देश्यों के लिये एक समिति की स्थापना का प्रश्न ही नही उठता।

उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा उप-कुलपति के पद पर कार्य किया जाना

2005. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूतपूर्व भारतीय सिविल सेवा अधिकारी उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जिन कारणों से उन्हें सेवा से मुक्त होने के लिये बाध्य किया गया उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भूतपूर्व आई० सी० एस० अधिकारी, श्री सी० बी० राव इस समय आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत कारणों के आधार पर 1 अक्तूबर, 1954 को आई० सी० एस० से सेवा निवृत्त हुए थे।

Import Programme for Fertiliser

2006. **SHRI MADHURYYA HALDAR** : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have finalized Fertilizer Import programme for the current year ;

(b) whether Government propose to import costly readymade NPK complex fertiliser from U. S. A. instead of local mixing of cheaper and staight fertilizer elements imported from abroad ; and

(c) whether his Ministry had any discussion with public sector technologists and Department of Economic Affairs on this issue ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) NPK complex fertilisers are imported to facilitate the market development programmes of domestic manufacturers, whose factories now under construction will be soon producing such fertiliser products. Contracts have already been entered into with the foreign suppliers for import of complex fertilisers to be allotted to these manufacturers during the year 1972-73.

The question regarding manufacture of NPK complex fertiliser indigenously by importing intermediates is being examined in the Department with reference to the comparative economies involved

(c) Yes, Sir The matter is under further consideration of the Ministry of Finance in consultation with the concerned Ministries.

नालों का सर्वेक्षण

2007. **श्री उमेद सिंह राठिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जशपुर तहसील मे तकमुदा गांव के निकट कोरिया नाला, कसबेल गांव के निकट घुघरी नाला और रायकेरा गांव के निकट गुलजरिया नाले का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उक्त सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वित करने के लिये सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी तथा निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० शेर

सिंह): (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सर्वेक्षण तथा लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के लिये धनराशि प्रचलित प्रतिमान के अनुसार ऋण तथा अनुदान एक मुश्त धनराशि में प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनावार कोई धनराशि नहीं दी जाती है। किसी विशेष ग्राम या जिले को प्रभावित करने वाली किसी विशेष सिंचाई योजना को शुरू करना पूर्णतः राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः इस प्रश्न में पूछी गई जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

जिला रायगढ़ (मध्य प्रदेश) में छाल तालाब पर तटबन्ध

2008 **श्री उमेद सिंह राठिया**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले की धर्मजय गढ़ तहसील में छाल तालाब पर तटबन्ध बनाने पर कितनी लागत आई और इससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जा रही है ;

(ख) क्या छाल ग्राम में तालाब पर तटबन्ध बनाने का काम पूरा हो गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा और इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये धनराशि, वर्तमान प्रणाली के अनुसार एक मुश्त ऋण तथा अनुदान के रूप में देती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनावार कोई भी स्वीकृति नहीं दी जाती है। किसी विशिष्ट गांव अथवा जिले की किसी विशेष सिंचाई योजना को प्रारम्भ करने का निर्णय पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अतः प्रश्न में मांगी गई जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

Request of Central Assistance for Lift Irrigation Schemes in U. P.

2009. **SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH**: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of lift-irrigation schemes for which the Uttar Pradesh Government has asked for Central Government's assistance ;

(b) the sites of these schemes ; and

(c) the decision of the Central Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) No such proposal has been received from Uttar Pradesh Government for Central assistance.

(b) and (c). Do not arise.

Setting Up of Water Boards to Tackle Drinking Water Problem in Rural and Urban Areas

2010. **SHRI B. K. DASCHOWDHURI : SHRI M. S. SIVASWAMY** :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether some States have set up Water Boards to tackle the drinking water problems in rural and urban areas ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the progress achieved in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Appointments to Tribal Development Blocks

2011. **SHRI DASARATHA DEB** : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the reason for not appointing any single tribal to the posts of Block Development Officer and Project Officer in the Tribal Development Blocks of Tripura, though there is no dearth of Tribal Graduates in Tripura ; and

(b) whether Central Government propose to investigate the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) The State Government have intimated that the posts of Project Executive officer and